ABN-AMRO Bank *v.* the Punjab Urban Planning and2633
Development Authority (Swatanter Kumar, J.)

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के समक्ष

एबीएन-एमरो बैंक,-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण- उत्तरदाता

सी. आर. सं. 2703 वर्ष 1997

22 जुलाई, 1999

संविदा अधिनियम, 1872- धारा 13 से 19ए- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 7 नियम 11- वादपत्र ख़ारिज करने बाबत -वादकारण- बैंक के खिलाफ पुडा का वाद बाबत वसूली -प्रतिवादी बैंक ने ज़रिए आवेदन पत्र अनतर्गत धारा 151 सी. पी. सी. सहपठित आदेश.7 नियम.॥ वादपत्र ख़ारिज करने का निवेदन किया-विचारणीय न्यायल्य द्वारा आवेदन खारिज किया गया-पुनरीक्षण में तर्क दिया कि पुडा द्वारा बताए गए कुछ तथ्यों के आधार पर उनके पक्ष में वादकरण उत्पन्न नहीं हुआ- आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन को निस्तारित करते समय विचारणीय न्यायाल्य वाद एवं सहायक दस्तावेजों का अवलोकन कर सकते हैं-प्रतिवादी द्वारा स्थापित बचाव के कोण से वादकारण को नहीं देखा जाता- जहां वादकारण स्पष्ट किया जाता है, पुनरीक्षण न्यायालय इस स्तर पर बचाव पर विचार नहीं करेगा-निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया।

यह अभिनिर्धारित किया कि वादपत्र ख़ारिज करने की याचिका "प्ली ऑफ डिमरर" पर आधारित है। इस तरह की याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को प्रतिद्वंद्वी द्वारा बताए गए तथ्यों को सही मानना होगा। उक्त शुद्धता की अस्थायी स्वीकृति के बावजूद, वादपत्र पूर्ण या आंशिक रूप से वादकारण का खुलासा नहीं करता है या चाहा गया अनुतोष कानून द्वारा वर्जित है तो वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज होने के लायक़ है। उक्त नियम के प्रथम दृष्टया अवलोकन से से दृष्टिगत होता है कि उक्त प्रावधान के तहत एक आवेदन के निर्धारण के लिए, न्यायालय को वादपत्र पर गौर करना होगा।इस अवधारणा को विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक निर्णय द्वारा इस प्रकार विस्तारित किया गया है की वादी द्वारा दायर दस्तावेज जो कि वाद के साथ या उसके बाद उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई से पूर्व दायर किए गए हो, को भी इसके दायरे में लिया जा सके। यह अधिक होगा-जहां दस्तावेजों को शिकायत में ही संदर्भित किया गया है।लेकिन प्रतिवादियों द्वारा अपने जवाबदावा में या उसके साथ दायर किए गए दस्तावेजों में उठाया गया बचाव निश्चित रूप से विचार के क्षेत्र से परे है। उक्त नियम की भाषा संदेह के लिए किसी भी ऐसी गुंजाइश को स्वीकार नहीं करती है कि प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान को ऐसे आवेदन के निर्णय के लिए आवेदकों द्वारा संदर्भित या भरोसा नहीं किया जा सकता है।क्या वादपत्र किसी वादकरण का खुलासा करता है या नहीं, यह एक सवाल है जो वादी द्वारा उक्त के वाद में अभिलिखित मुख्य वादकारण पर आधारित है।इस प्रकार नियम 11 केवल वादपत्र व सहायक दस्तावेज़ो तक ही सीमित है।

(पैरा 7)

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि इस न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रतिवादी आवेदक-याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन के गुणावगुण को निर्धारित करने के लिए वाद एवं सहायक दस्तावेज जो की अभिलेख पर हैं, और विशेष रूप से

उन दस्तावेजों पर ध्यान देना चाहिए, जिन्हें वाद में संदर्भित किया गया है।

(पैरा 8)

यह भी अभिनिर्धारित किया कि किसी भी मामले में वाद पत्र सीमित रूप से वादी बैंक के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ वादकारण का खुलासा करता है।इस दावे की योग्यता क्या होगी, यह फिर से एक सवाल है जिस पर अदालत को उचित स्तर पर और साक्ष्य के समापन पर विचार करना होगा।वादपत्र की आंशिक अस्वीकृति अनुज्ञेय नहीं है।सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों का उद्देश्य उस नियम में बताए गए सीमित आधारों पर पहले चरण में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करना है।

(पैरा 21)

यह अभिनिर्धारित किया कि आंशिक अस्वीकृति की अवधारणा स्पष्ट रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों पर लागू नहीं होती है, संहिता के आदेश 6 नियम 16 के प्रावधानों के संबंध में इसका सीमित अनुप्रयोग होगा।दलीलों पर आंशिक रूप से प्रहार किया जा सकता है लेकिन वाद की अस्वीकृति नहीं।आंशिक स्वीकृति या अस्वीकृति या यहां तक कि उस प्रभाव के लिए एक विशिष्ट नियम के अभाव में अपीलों की स्वीकृति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार में नहीं होना बताया गया था।

(पैरा 22)

यह अभिनिर्धारित किया कि वादकारण स्पष्ट करने के लिए, एक वादपत्र में वादी को उचित शर्तों का उल्लेख करना चाहिए।ऐसे आवेदन पर विचार करने के लिए उन शर्तों या शर्तों की योग्यता इस स्तर पर महत्वहीन है।वादी अपने वाद को साबित करने के लिए क्या सबूत देगा या प्रतिवादी क्या संभावित बचाव करेगा, यह कार्यवाही के उस प्रारंभिक चरण में नहीं देखा जाना।कारण सामान्य शब्द है।प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मध्यनज़र इसे निर्मित किया जाना चाहिए।मुकदमों में की गई कार्यवाही न्यायोचित है और मामले के तथ्यों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है

(पैरा 23)

वरिष्ठ अधिवक्ता वी. एन. कौरा, सहायक अधिवक्ता परमजीत बेनीपाल और रोहित सप्रा के साथ, वास्ते याचिकाकर्ता

अधिवक्ता एच. एस. अवस्थी सहायक अधिवक्ता अमित के साथ-वास्ते प्रत्यर्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार,

(1) 15 जून, 1996 को या उसके आसपास पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण ने वाद बाबत वसूली रुपये 65,58,981.00 मय फ्यूचर ब्याज @ 17% एवं वास्ते घोषणा कि वादी द्वारा प्रतिवादी को लिखा गया 7 जुलाई, 1993 का इक्रारनामा/छूट पत्र वादी पर बाध्यकारी नहीं था।समन भेजने पर, प्रतिवादी ने 26 सितंबर, 1996 को उपरोक्त मुकदमे में वाद की अस्वीकृति के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदनपत्र दायर किया।इस आवेदन में, प्रतिवादी ने वादपत्र की अस्वीकृति की अपनी याचिका को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित आधार लिए थेः—

1. इस आवेदन के उद्देश्य के लिए यह कहना पर्याप्त है कि वादी का वाद मुख्यतः इस घोषणा के लिए है कि 7 जुलाई, 1993 को आवास आयुक्त द्वारा वास्ते पंजाब आवास विकास बोर्ड, पंजाब सरकार, प्रतिवादी बैंक को संबोधित एक पत्र में दर्ज किया गया समझौता अमान्य है, जो कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 15 में परिभाषित जबरदस्ती से प्राप्त किया गया था, और इसके परिणामस्वरूप रुपये 65, 58, 981.04/- की क्षतिपूर्ति का दावा किया गया
2. प्रतिवादी प्रस्तुत करता है कि वाद यह घोषणात्मक अनुतोष चाहने के अभाव में कि पंजाब आवास विकास बोर्ड के लिए किया गया उपरोक्त समझौता अमान्य है व रद्द करने हेतु पोषणीय नहीं है।''

(2)आवेदन का जवाब प्रदतुत किया गया और वादी द्वारा इसका विरोध किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय,-4 मार्च, 1997 के अपने आदेश के माध्यम से प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया और दस्तावेजों की स्वीकृति वि अस्वीकृति हेतु वादी के आवेदन को स्वीकार किया। दिनांक 4 मार्च, 1997 के विवादित आदेश का समापन भाग इस प्रकार हैः—

"दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान वकील ने जबरन तर्क दिया कि यह फिर से सबूत लेने के बाद तय किया जाना चाहिए कि क्या 7 जुलाई, 1993 को एक नया अनुबंध पत्र विकसित किया गया है।और मैं सहमत हूँ

प्रत्यर्थी/वादी के वकील द्वारा की गई दलीलें।इसमें कोई संदेह नहीं है कि आवेदक/प्रतिवादी वकील द्वारा उल्लिखित अधिकारी विवादित नहीं हैं, लेकिन उनके आवेदन पर अंतिम बहस के समय ही विचार किया जाएगा।

XXXXXX

इस स्तर पर, वादी का मुकदमा पूरी तरह से तुच्छ नहीं लगता है और विवाद में मामले का फैसला करने के लिए सबूत बुलाए जाने चाहिए और शिकायत में उल्लिखित तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है।दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी लड़ने की बात आती है कि आवेदक/प्रतिवादी ने कभी भी इन बांडों को नहीं खरीदा और इसने दस्तावेजों की शर्तों का उल्लंघन किया।विचारणीय मुद्दे हैं और शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता है।आवेदक/प्रतिवादी ने अभी तक लिखित बयान दायर नहीं किया है जिसका अर्थ है कि इस स्तर पर वाद में किए गए सभी कथनों को सही माना जाना चाहिए।वादी में कोई अवैधता नहीं है और इसे इस स्तर पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए दी गई परिस्थितियों में, सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया जाता है और वादी को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के लिए आवेदन की भी अनुमति दी जाती है।"

(2) चूंकि अदालत द्वारा मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए विद्वत निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही जारी रही और प्रतिवादी ने 30 अप्रैल, 1997 को अपना लिखित बयान दायर किया।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में कई प्रारंभिक आपत्तियां ली गई हैं।अन्य बातों के अलावा, विशिष्ट प्रारंभिक आपत्तियों को इस आधार पर लिया गया है कि मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था और लिखित बयान में किए गए अभिकथनों के आधार पर सहमति और संतुष्टि, छूट और

बहिष्कार द्वारा वर्जित था।रोक लगाने की याचिका और कार्रवाई के उचित कारण का खुलासा नहीं करने वाली शिकायत भी की गई है।वादी द्वारा दायर प्रतिकृति में इन प्रारंभिक आपत्तियों का खंडन किया गया है।

(3) याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि विद्वत निचली अदालत प्रतिवादी के आवेदन को खारिज करने में अधिकार क्षेत्र की त्रुटि में पड़ गई है।यह तर्क दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रतिवादी को लिखे गए 7 जुलाई, 1993 के पत्र के संदर्भ में भुगतान स्वीकार करके और विशेष रूप से ऐसी राशि की बिना शर्त स्वीकृति प्रतिवादी को किसी भी दायित्व से मुक्त करती है।मुकदमे को जारी रखने को सही ठहराने के लिए शिकायत में गलत तरीके से प्रस्तुत करने, धोखाधड़ी या जबरदस्ती के अनुरोध पर कार्रवाई के उपलब्ध कारण का गठन करने वाले किसी भी तथ्य का अनुरोध नहीं किया गया है।दूसरे शब्दों में, वादपत्र कानून की नजर में किसी भी वादकारण का खुलासा नहीं करता है।इस उद्देश्य के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने पत्र दिनांकित 7 जुलाई, 1993 के निम्नलिखित भागों का उल्लेख किया:

(2)) और जहां कि, परिणामस्वरूप बैंक और बोर्ड के बीच लंबी बातचीत हुई है, जिसके फलस्वरूप यह सहमति हुई है कि बैंक तुरंत मूलधन राशि रुपये 9,75,58,904.11/- को बोर्ड केकी वापस कर देगा।ब्याज की गणना 3 सितंबर, 1992 तक के पहले छह महीनों के लिए 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से की जाएगी जो की रुपए 82,92,507/- (जो हमें पहले ही प्राप्त हो चुका है) और शेष अवधि यानी 4 सितंबर, 1992 से मूलधन राशि के भुगतान की तारीख तक, ब्याज का भुगतान इस अवधि की देय सावधि जमा दर पर किया जाएगा, जिसकी गणना 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कर राशि रुपए 1,02,23,638/- होगी। इसके अतिरिक्त जब भी आई. आर. एफ. सी. बांड बैंक ऑफ आंध्र बैंक के नाम से हस्तांतरित किए जाते हैं, तो बैंक ब्याज के साथ बैंक को देय धन लौटाता है, बैंक अतिरिक्त रूप से 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर और शेष अवधि के लिए सावधि जमा दर के बीच के ब्याज अंतर का भुगतान करेगा, यानी 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की राशि रुपये 36,80,510 है। इस अंतर राशि रुपये 36,80,510 पर ब्याज का भुगतान बैंक द्वारा हमें उस अवधि की सावधि जमाओं पर लागू दर पर किया जाएगा, जिसके लिए बैंक द्वारा राशि रखी जाती है, इस पैरा के प्रावधानों के अनुसार, जो ऊपर बताए गए हैं, बशर्ते कि बैंक भी अपने ब्याज दावों पर इसी तरह ब्याज प्राप्त करे।

ऊपर बताए गए इस पैराग्राफ के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड उक्त निवेश के संबंध में उत्पन्न होने वाले अपने दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में उपरोक्त भुगतान को स्वीकार करेगा और जिसके लिए बोर्ड बैंक को एक अस्वीकरण और छूट प्रदान करेगा जैसा कि इसके बाद दिखाई देगा।

कि बैंक समय-समय पर, और महीने में कम से कम एक बार नहीं, इन आई. आर. एफ. सी. बांडों की खरीद से उत्पन्न दावों के निपटारे के मामले में की गई स्थिति और प्रगति को सूचित करेगा।

(9) और जहां उक्त समझौते के अनुसार, बैंक ने बोर्ड को रु। उक्त निवेश से या उसके संबंध में बैंक के खिलाफ बोर्ड के दावों के पूर्ण और अंतिम निपटारे में (जिसकी रसीद, जैसा कि ऊपर कहा गया है, पूर्ण और अंतिम निपटान में, बोर्ड एतद्द्वारा स्वीकार करता है और स्वीकार करता है), और इसके परिणामस्वरूप बोर्ड

निर्वहन और छूट को निष्पादित कर रहा है जैसा कि इसके बाद दिखाई दे रहा है।

(10) अब वहाँ, हम पंजाब आवास विकास बोर्ड, आवास आयुक्त, पंजाब आवास विकास बोर्ड के माध्यम से कार्य करते हुए रुपये 10,77,82,542.11 (दस करोड़ सत्ताईस लाख अस्सी हजार पाँच सौ बयालीस और ग्यारह पैसे मात्र) पंजाब आवास विकास बोर्ड के सभी दावों जो की रुपये 9,75,58,904.11/- इन्वेस्टमेंट से संबंधित हैं, के पूर्ण और अंतिम निपटारे हेतु स्वीकार करते हैं और यह पुष्टि एवं घोषणा करते हैं कि बैंक अपने विवेकाधिकार पर मांग करने, मुकदमा करने, लागू करने, समझौता करने या अन्यथा किसी भी और उससे संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए हकदार होगा, जिसमें ऐसी मांग, वाद प्रवर्तन, निपटान, समझौता या अन्य लेन-देन (ओं) के उपयोग, आय या लाभ के संबंध में बोर्ड में कोई अधिकार नहीं होगा और बोर्ड इसके द्वारा बैंक के पक्ष में किसी भी और सभी अधिकारों और दावों को अस्वीकार, माफ और त्याग देता है जो उसके संबंध में हो सकता है।"

(5) जबकि दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वादपत्र को रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों के साथ पढ़ा जाये तो वादी ने अपने वाद में वादकरण स्पष्ट किया है जिसे कि गुणवगुण प्पर वाद का विनिश्चय किया जा सके।उन्होंने यह भी

(6) तर्क दिया कि 7 जुलाई, 1993 का पत्र वास्तव में पक्षों के बीच बाद के पत्राचार द्वारा रद्द कर दिया गया था और अनुबंध अधिनियम की धारा 13 से 19ए के तहत बुनियादी अवयवों को संतुष्ट करने के लिए शिकायत में पर्याप्त आधार लिए गए हैं। ली गई दलीलें और उनके समर्थन में पढ़े गए दस्तावेज 7 जुलाई, 1993 के पत्र को अप्रभावी और अप्रासंगिक बनाते हैं।उन्होंने मुख्य रूप से 7 अगस्त, 1993 को ही वादी की ओर से प्रतिवादी को वकील द्वारा दिए गए नोटिस पर भरोसा किया।उन्होंने उक्त सूचना के निम्नलिखित पैराग्राफ में की गई दलीलों पर जोर दिया, जो इस प्रकार है:—

4. 13 मई, 1992 को हमारे ग्राहकों को बैंक से 12 मार्च, 1992 को एक पत्र मिला जिसमें सूचित किया गया था कि बैंक ने एन. पी. सी. बांड के बजाय आई. आर. एफ. सी. बांड खरीदे हैं, जिसमें प्रतिभूति के 9 प्रतिशत की कम उपज का उल्लेख नहीं किया गया था।जब हमारे ग्राहकों ने पत्र की पिछली तारीख के कारणों के बारे में पूछताछ की, तो उन्हें बैंक के अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि यह लिपिकीय त्रुटि थी और वास्तव में पत्र 12 मई, 1992 को लिखा गया था।

XXXXXX

(6) हमारे ग्राहकों ने 4 सितंबर, 1992 के अपने पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि उन्हें बैंक द्वारा आई. आर. एफ. सी. बांड की खरीद के बारे में सूचित किया गया था और आगे कहा कि बैंक ने उन्हें आश्वासन दिया था कि निवेश का लाभ समान होगा।उस समझ पर हमारे ग्राहकों को निवेश की अवधि को 180 दिनों तक बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया, बशर्ते कि पहले छह महीनों की उपज 17 प्रतिशत की दर से हो, जो रु। 82, 92, 507.00 उन्हें तुरंत भेज दिया गया।17 प्रतिशत की दर से यह ब्याज लाभ हमारे ग्राहकों को प्रेषित किया गया था और उसके बाद निवेश को 180 दिनों की आगे की अवधि यानी 3 मार्च, 1993 तक जारी रखा गया था।पहले छह महीनों के लिए 17 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने से हमारे ग्राहकों को विश्वास हो गया कि उन्हें भविष्य की अवधि के लिए भी 17 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा।XXXXXX

(9) हमारे ग्राहकों को छूट पत्र निष्पादित करने के लिए कहा गया था।बाध्यकारी

परिस्थितियों में और उन शर्तों के विपरीत कार्य करते हुए बैंक द्वारा बनाई गई स्थिति के कारण, जिनके तहत हमारे ग्राहक निवेश करने के लिए सहमत हुए थे, हमारे ग्राहकों के पास आपकी इच्छा के अनुसार 7 जुलाई, 1993 का छूट पत्र जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह छूट पत्र हमारे ग्राहकों द्वारा मुफ्त सहमति के बिना निष्पादित किया गया था।किसी भी स्थिति में हमारे ग्राहक दावा करते हैं कि जो छूट पत्र स्वीकार नहीं किया गया है वह अमान्य, गलत और अप्रभावी है।हमारे मुवक्किलों ने हमें 7 जुलाई, 1993 के छूट पत्र को वापस लेने, रद्द करने, रद्द करने और रद्द करने का निर्देश दिया है।

(6) वनहीन जटिल तथ्यों से उत्पन्न होने वाला पहला विवाद यह है कि क्या न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत किसी आवेदन की योग्यता निर्धारित करने के लिए अकेले वाद पर विचार करना है या उसे संबंधित पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों की जांच करनी है।

(7) यह कानून का एक तय नियम है कि वादपत्र की अस्वीकृति की याचिका "प्ली ऑफ़ डिमुरर" पर आधारित है।इस तरह की याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को प्रतिद्वंद्वी द्वारा बताए गए तथ्यों को सही मानना होगा। उक्त शुद्धता की अस्थायी स्वीकृति के बावजूद, वादपत्र पूर्ण या आंशिक रूप से वादकारण का खुलासा नहीं करता है या चाहा गया अनुतोष कानून द्वारा वर्जित है तो वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज होने के लायक़ है। उक्त नियम के प्रथम दृष्टया अवलोकन से से दृष्टिगत होता है कि उक्त प्रावधान के तहत एक आवेदन के निर्धारण के लिए, न्यायालय को वादपत्र पर गौर करना होगा।इस अवधारणा को विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक निर्णय द्वारा इस प्रकार विस्तारित किया गया है की वादी द्वारा दायर दस्तावेज जो कि वाद के साथ या उसके बाद उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई से पूर्व दायर किए गए हो, को भी इसके दायरे में लिया जा सके। यह अधिक होगा-जहां दस्तावेजों को शिकायत में ही संदर्भित किया गया है।लेकिन प्रतिवादियों द्वारा अपने जवाबदावा में या उसके साथ दायर किए गए दस्तावेजों में उठाया गया बचाव निश्चित रूप से विचार के क्षेत्र से परे है। उक्त नियम की भाषा संदेह के लिए किसी भी ऐसी गुंजाइश को स्वीकार नहीं करती है कि प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान को ऐसे आवेदन के निर्णय के लिए आवेदकों द्वारा संदर्भित या भरोसा नहीं किया जा सकता है।क्या वादपत्र किसी वादकरण का खुलासा करता है या नहीं, यह एक सवाल है जो वादी द्वारा उक्त के वाद में अभिलिखित मुख्य वादकारण पर आधारित है।इस प्रकार नियम 11 केवल वादपत्र व सहायक दस्तावेज़ो तक ही सीमित है।हरनाम सिंह बनाम सुरजीत सिंह (1) के मामले में इस न्यायल्य की एक पूर्ण पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:—

"यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कार्रवाई के कारण का अर्थ है प्रत्येक तथ्य जो, यदि पार किया जाता है, तो वादी के लिए अपने पक्ष में निर्णय के अधिकार का समर्थन करने के लिए साबित करना आवश्यक होगा।दूसरे शब्दों में कहें तो!यह तथ्यों का एक समूह है जो उन पर लागू कानून के साथ लिया जाता है जो वादी को किरायेदार के खिलाफ राहत का अधिकार देता है।नकारात्मक रूप से इसमें तथ्यों के बंडल को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य शामिल नहीं है और समान रूप से बचाव पक्ष से कोई संबंध नहीं है, जिसे प्रतिवादी द्वारा स्थापित किया जा सकता है और न ही यह वादी द्वारा राहत की प्रार्थना के चरित्र पर निर्भर करता है।"

(8) उपरोक्त दृष्टिकोण को सभी न्यायालयों ने स्वीकार कर लिया है।इस संबंध में श्रीमती प्रमीला खोसला बनाम रजनीश कुमार खोसला (2), भगवान दास बनाम गोस्वामी बृजेश कुमारजी वि अन्य (3), दोसल प्राइवेट लिमिटेड वि अन्य बनाम नर्मदा सीवेज लिमिटेड वि अन्य (4) मामलों का उल्लेख किया जा सकता है।इस प्रकार, मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रतिवादी-आवेदक-याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन के गुण-दोष निर्धारित करने के लिए वाद और अभिलेख पर दायर दस्तावेजों और विशेष रूप से उन दस्तावेजों पर ध्यान देना चाहिए, जिन्हें वाद में संदर्भित किया गया है।

(9) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री वी. एन. कौरा ने तर्क दिया कि वादी के पास कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं है।सिविल न्यायालय ने पक्षकारों के बीच लेन-देन से उत्पन्न अपने दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान में एक पत्र निष्पादित किया था।वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया था

(1) ए. आई. आर. 1984 पी. बी. और हैरी। 126
(2) ए. आई. आर. 1979 दिल्ली 78
(3) ए. आई. आर. 1983 राजस्थान 3
(4) ए. आई. आर. 1989 बॉम्बे 96 और 1986 (2) पी. एल. आर. 219

श्री कौरा ने कहा कि धोखाधड़ी या गलत निरूपण के मूल तत्व न तो बताए गए हैं और न ही वाद में किए गए दावे वैध रूप से धोखाधड़ी, गलत निरूपण या अनुचित प्रभाव का आधार हैं और इस तरह से वाद कानूनी कार्रवाई के वैध कारण का खुलासा करता है।नतीजतन, शिकायत को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(10) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता, श्री अवस्थी ने तर्क दिया कि शिकायत और अभिलेख पर दायर दस्तावेज पूरी तरह से वादी के पक्ष में कार्रवाई योग्य कारणों का खुलासा करते हैं।उन्होंने आगे तर्क दिया कि संशोधन के लिए एक आवेदन पहले से ही निचली अदालत के समक्ष लंबित है जो स्वयं इस अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए कथित बचाव को विफल कर देगा।श्री अवस्थी द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि मामले को केवल पूर्ण साक्ष्य के समापन पर ही देखा जा सकता है न कि वर्तमान आवेदन दाखिल करने के माध्यम से।श्री अवस्थी ने तर्क दिया कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश इस न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के सीमित दायरे में किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

(11) सिविल न्यायशास्त्र के अच्छी तरह से स्वीकृत सिद्धांत "वादी को कोई वादकारण प्राप्त नहीं है" और "वादपत्र वादकारण का खुलासा नहीं करता है" के बीच स्पष्ट अंतर करते हैं।" पूर्ववर्ती भाग में मुकदमा करने के अधिकार का पूर्ण अभाव है।जबकि बाद में, मुकदमा करने का अधिकार मौजूद हो सकता है, लेकिन यह वाद में किए गए कथनों के आधार पर अच्छी तरह से स्थापित नहीं है।वाद-पत्र में आवश्यक और भौतिक विवरणों का अभाव है जो वादी को कार्रवाई का एक प्रभावी कारण देगा।जहां इसके बावजूद, शिकायत "कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है, शिकायत खारिज होने के लिए उत्तरदायी हो सकती है, लेकिन जहां पक्षों को शिकायत में दावा की गई कार्रवाई और राहत के अपने कारण को साबित करने और समर्थन करने के लिए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश करना है, अदालत को रिकॉर्ड पर रखी गई पूरी सामग्री पर विचार करना होगा और मुकदमा योग्यता के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

(12) उपरोक्त अंतर जगन्नाथ प्रसाद व अन्य बनाम श्रीमती चन्द्रावती व अन्य(5) के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया था।

(13) हाल के एक मामले उड़ीसा राज्य बनाम क्लॉक्नर एंड कंपनी व अन्य (6) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए निम्नलिखित दृष्टिकोण को मंजूरी देते हुए विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।

> "आदेश में की गई चर्चाओं से यह प्रतीत होता है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने इस दलील में अंतर नहीं रखा है कि वाद का कोई वादकरण नहीं था और

कि वादपत्र वादकारण का खुलासा नहीं करता है।आदेश में वादपत्र ख़ार्जा के निष्कर्ष के समर्थन में कोई विशिष्ट कारण या आधार नहीं कथित किया गया है कि वादपत्र को आदेश 7 नियम 11 (ए) के तहत खारिज क्यूँ किया जाना है।वादपत्र के कथनों से, यह स्पष्ट है कि वादी ने वाद दायर कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने के लिए वादकारण स्पष्ट किया है।इसका मतलब यह नहीं है कि वादी के पास वांछित अनुतोष बाबत वाद दायर करने का वादकारण है, इस प्रश्न का विनिश्चय उन सामग्रियों (वाद के अलावा) के आधार पर किया जाना है जिन्हें वाद में उचित स्तर पर पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।इस प्रश्न का निर्धारण करने के सीमित उद्देश्य के लिए कि क्या आदेश 7, नियम 11 (1) के तहत मुकदमे को ख़ारिज किया जाना है या नहीं, केवल वाद में किए गए कथनों पर विचार किया जाना है।ऊपर उल्लिखित स्थिति आदेश 7, नियम 11 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर याचिका से भी स्पष्ट है जिसमें मामले का जोर यह है कि 20 अप्रैल, 1982 के समझौते की शर्तों पर वादी वादपत्र में वर्णित किसी भी राहत के लिए मुकदमा दायर करने का हकदार नहीं है।"

(14) उपर्युक्त सुस्थापित सिध्दांतो के मध्यनज़र, पत्र दिनांकित 7 जुलाई, 1993 के अभिकथनों पर गौर करना है, जो आवेदक के अनुसार वादी के मुकदमा करने के अधिकार को नकारता है, क्योंकि रु 9 करोड़ रुपये से अधिक के उक्त निवेश के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले पंजाब आवास विकास बोर्ड (वादी) के सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में रुपए 10,4,82,542.11 पैसे ले लिये गये थे।वादपत्र को प्रथम दृष्टया पढ़ने से ही पता चलता है कि वादी ने 7 जुलाई, 1993 के पत्र की वैधता, वाद्यता को चुनौती दी है और वादपत्र के पैराग्राफ 20 में इसे रद्द करने का अनुरोध किया है।यह अनुरोध किया जाता है कि उक्त पत्र वादी के कुल राशि की वसूली के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है।बोर्ड ने रुपये 65,58,981 की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है।वादी ने वर्तमान याचिकाकर्ता की ओर से गलत प्रतिनिधित्व, तथ्यों को छिपाने और धोखाधड़ी के आचरण का आधार लिया है।पक्षकारों के बीच निष्पादित विशिष्ट दस्तावेजों के संदर्भ के अलावा, 7 अगस्त, 1993 के नोटिस का एक संदर्भ दिया गया है, जिसे बोर्ड ने अपने वकील के माध्यम से याचिकाकर्ता पर 7 जुलाई, 1993 के पत्र को वापस लेने और प्रतिवादी (याचिकाकर्ता) को अपनी राशि का भुगतान करने के लिए कहने पर दिया था।मुकदमे की स्थिरता और छूट और निष्कासन की याचिका के संबंध में विभिन्न प्रारंभिक आपत्तियां ली गई हैं।दूसरे शब्दों में, पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर रखे गए विभिन्न दस्तावेज और विशेष रूप से वाद में संदर्भित दस्तावेज, जो वाद में किए गए कथनों के साथ उनके सहायक पठन पर होते हैं, परीक्षण योग्य मुद्दों को उठाते हैं जिन पर पक्षकार पूर्ण और आवश्यक साक्ष्य का नेतृत्व करेंगे।

(15) इस स्तर पर, इस न्यायालय के लिए यह बहुत उचित नहीं हो सकता है कि वह कार्यवाही के किसी भी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह से बचने के लिए पक्षों के अभिवचनों पर आधारित प्रत्येक दस्तावेज से उत्पन्न होने वाले प्रभाव और परिणामों पर चर्चा करे।वादी अंततः सफल होगा या नहीं, यह एक उचित मुद्दा तैयार करके निर्धारित किया जाने वाला सवाल है, लेकिन यह कहना कि बताए गए तथ्यों और उनके समर्थन में दस्तावेजों पर शिकायत, कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है, शायद ही कायम रह सकती है।

(16) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कपूर चंद गोधा बनाम मीर नवाब हिमायतीखान, आजमगढ़ (7) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि यहां प्रतिवादी ने 7 जुलाई, 1993 के अपने पत्र के माध्यम से

पूर्ण निर्वहन दिया था और उनके दावे पर पूर्ण संतुष्टि के साथ विचार प्राप्त किया था।प्रत्यर्थी के बिना शर्त भुगतान स्वीकार करने पर कार्रवाई का कोई कारण नहीं है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के बाद मामले से संबंधित था और नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा एक डिक्री पारित की गई थी।न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के दायरे और दायरे में शिकायत की अस्वीकृति से संबंधित नहीं था।तथ्यों पर भी, पूर्ण और अंतिम समझौते के दस्तावेज़ के निष्पादन के संबंध में धोखाधड़ी, गलत प्रतिनिधित्व और अनुचित प्रभाव के आधार पर कोई चुनौती नहीं थी।

(17) अन्य निर्णय जिस पर विद्वान वकील ने अपने वैकल्पिक तर्कों के समर्थन में उल्लिखित किया है, वह है बिशुंडू नारायण व अन्य बनाम सेओगेनी राय व अन्य।(8), जहाँ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः—

> "धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती के मामले में, इसका अनुरोध करने वाले पक्षों को पूरा विवरण देना चाहिए और मामले का निर्णय केवल निर्धारित विवरणों पर ही किया जा सकता है।साक्ष्य में उनसे कोई विचलन नहीं हो सकता है।सामान्य आरोप धोखाधड़ी के एक प्रमाण के रूप में भी अपर्याप्त हैं, जिस पर किसी भी सी. टी. को ध्यान देना चाहिए, भले ही वे जिस भाषा में बोले गए हों, वह कितनी भी मजबूत हो, और यही अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती पर लागू होता है।"

पुनः इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे मामले से संबंधित था जिसमें निर्णय और डिक्री पहले ही सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा तैयार की जा चुकी थी और यहां तक कि अपीलीय न्यायालय ने भी निर्णय और डिक्री पारित कर दी थी।

(7)ए. आई. आर. 1963 (2) एस. सी. 168.

(8)ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 280.

(19) वादी द्वारा अभिलेख पर दाखिल दस्तावेजों के आलोक में देखे गए वाद के उपरोक्त पैराग्राफ, विशेष रूप से नोटिस और अभिकथन कि यह पूरी तरह से याचिकाकर्ता द्वारा सार्वजनिक धन वापस करने से इनकार करने और जनता को मसौदे के अनुसार एक पत्र पर हस्ताक्षर करने का आदेश देने के अनुचित प्रभाव के कारण था, को कोई अभिवचन नहीं होने या जहां वादी कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताती है, का मामला नहीं कहा जा सकता है।न्यायालय को दस्तावेजों द्वारा समर्थित वाद में अनुरोध किए गए मामले के संचयी प्रभाव को देखना चाहिए, यदि वादी द्वारा दायर किया गया है, तो सीमित दायरे के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले परिणामों की समग्रता की जांच करने के लिए और इस न्यायालय के लिए प्रतिवादियों के बचाव को ध्यान में रखना न तो अनुमेय है और न ही उचित है।विद्वत विचारण न्यायालय ने वादी को साक्ष्य देने की अनुमति दी है और छूट और अवरोध के साथ-साथ पक्षों के बीच धोखाधड़ी और गलत प्रतिनिधित्व के घटकों के संबंध में प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिकाकर्ता के हित की रक्षा की है।

(20) शिकायत में यह दलील दी गई है कि वादी को सहमत ब्याज दर का भी भुगतान नहीं किया गया था और न ही वादी को 7 जुलाई, 1993 के पत्र के संदर्भ में भी किसी भी राशि की वसूली के बारे में सूचित किया गया था।7 जुलाई, 1993 के पत्र के पैरा 8 में कहा गया थाः—

"(8) और इसके परिणामस्वरूप बैंक और बोर्ड के बीच लंबी बातचीत हुई है जिसके परिणामस्वरूप यह सहमति हुई है कि बैंक तुरंत 500 करोड़ रुपये की मूलधन राशि वापस कर देगा। 9,75,58,904.11 बोर्ड को।ब्याज की गणना 3 सितंबर, 1992 तक के पहले छह महीनों के लिए 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से की जाएगी। 82,92,507 (जो हमें पहले ही प्राप्त हो चुका है) और शेष अवधि यानी 4 सितंबर, 1992 से मूलधन राशि के भुगतान की तारीख तक, इस अवधि की सावधि जमा पर देय दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जिसकी गणना 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से की जाती है। 1,02,23,638।इसके अलावा जब भी आई. आर. एफ. सी. बांड बैंक ऑफ आंध्र बैंक के नाम से हस्तांतरित किए जाते हैं, तो बैंक ब्याज के साथ बैंक को देय धन लौटाता है, बैंक अतिरिक्त रूप से 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर और शेष अवधि के लिए सावधि जमा दर के बीच के ब्याज अंतर का भुगतान करेगा, जो 12 प्रतिशत प्रति वर्ष है। 36,80,510।रुपये की इस अंतर राशि पर ब्याज। 36,80,510 का भुगतान बैंक द्वारा हमें उस अवधि की सावधि जमाओं पर लागू होने वाली तारीख पर किया जाएगा, जिसके लिए बैंक द्वारा राशि रखी जाती है, इस पैरा के प्रावधानों के अनुसार, जो ऊपर बताए गए हैं, बशर्ते कि बैंक भी अपने ब्याज दावों पर इसी तरह ब्याज प्राप्त करे।

ऊपर बताए गए इस पैराग्राफ के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड उक्त निवेश से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले अपने दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में उपरोक्त भुगतान को स्वीकार करेगा, और जिसके लिए बोर्ड बैंक को एक अस्वीकरण और छूट प्रदान करेगा जैसा कि इसके बाद दिखाई देगा।

कि बैंक समय-समय पर, और महीने में कम से कम एक बार, इन आई. आर. एफ. सी. बांडों की खरीद से उत्पन्न दावों के निपटारे के मामले में की गई स्थिति और प्रगति को सूचित करेगा।"

(21) इस प्रकार, वादी बैंक का उपरोक्त सीमित सीमा तक राशि की वसूली करने का अधिकार, भले ही यह माना जाता है कि 7 जुलाई, 1993 का पत्र वैध और उचित है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राशि शिकायत में दावा की गई राशि से कम है।इस प्रकार, किसी भी मामले में सीमित सीमा तक वाद वादी बैंक के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है।इस दावे की योग्यता क्या होगी, यह फिर से एक सवाल है जिस पर अदालत को उचित स्तर पर और साक्ष्य के समापन पर विचार करना होगा।अभियोग की आंशिक अस्वीकृति फिर से अनुज्ञेय नहीं है।सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों का उद्देश्य अंततः अधिकारों का निर्धारण करना है।उस नियम में बताए गए सीमित आधारों पर पहले के चरण में पक्षों की।बंसी लाई बनाम सोम प्रकाश और अन्य (9) के मामले में इस न्यायालय की एक पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः—

"यह नियम (0.7 आर. 11) वाद के किसी विशेष भाग की अस्वीकृति को उचित नहीं ठहराता है।" इस कथन के समर्थन में विद्वान लेखक ने रघुबंस पुरी बनाम ज्योतिस स्वरूप, 29 ऑल 325, अप्पो राव बनाम राज्य सचिव, 54 मैड 416, और मकसूद अहमद बनाम मथुरा दत्त एंड कंपनी, ए. आई. आर. (23) 1936 लाह 1021 पर भरोसा **किया है।**

इसलिए मेरी राय है कि विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने एक हिस्से के रूप में अस्वीकृति को बरकरार रखने और अस्वीकृति को दूसरे हिस्से में अलग रखने में गलती की थी।इस अपील को जिसे मैं पुनरीक्षण के लिए एक याचिका के रूप में मान रहा हूं, इसलिए इसकी अनुमति दी जानी चाहिए और नियम को पूर्ण बनाया जाना चाहिए, और मैं तदनुसार आदेश देता हूं।"

(22) आंशिक अस्वीकृति की अवधारणा स्पष्ट रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों पर लागू नहीं होती है, आदेश के प्रावधानों के संबंध में इसका सीमित अनुप्रयोग होगा।6 संहिता का नियम 16।दलीलों पर आंशिक रूप से प्रहार किया जा सकता है लेकिन वाद की अस्वीकृति नहीं।आंशिक स्वीकृति या अस्वीकृति या यहां तक कि उस प्रभाव के लिए एक विशिष्ट नियम के अभाव में अपीलों की स्वीकृति थी

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्णित अधिकार क्षेत्र का उचित प्रयोग नहीं है।इस संबंध में, रामजी भागला बनाम कृष्णराव करीराव बागरे और एक अन्य (10) के मामले का संदर्भ दिया जा सकता है।यह वर्तमान मामले में पक्षों के बीच मुख्य विवाद भी नहीं है।इस प्रकार, मुझे आगे किसी भी भ्रम में इस विवाद पर चर्चा करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

(23) वादकारण को दर्शाने के लिए, एक वादी को मुकदमे को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्वों का उल्लेख करना चाहिए।ऐसे आवेदन पर विचार करने के लिए उन तत्वों अथवा शर्तों और/या शर्तों की योग्यता इस स्तर पर महत्वहीन है।वादी अपने मामले को साबित करने के लिए क्या सबूत देगा या प्रतिवादी क्या संभावित बचाव करेगा, यह कार्यवाही के उस प्रारंभिक चरण में अदालत की चिंता नहीं है।कारण उचित सामान्य शब्द है।प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसके निर्माण का निर्णय लिया जाना चाहिए।मुकदमों में उठाए गए कदम कानूनी रूप से उचित हैं और मामले के तथ्यों पर, वे विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को फिर से लेने की आवश्यकता नहीं मानते हैं।

(24) मैं इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हूं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस स्तर पर आवेदन को खारिज करने में अधिकारिता की त्रुटि की गई है और यह अभिनिर्धारित करता हूँ कि वाद में ऐसे विचारण योग्य बिंदु हैं जिन्हें इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है और पक्षों को अपने साक्ष्य को समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।4 मार्च, 1997 के विवादित आदेश में अधिकारिता या अन्यथा कोई त्रुटि पाने में असमर्थ होने से, मुझे इस पुनरीक्षण के आवेदन को खारिज करने में कोई संकोच नहीं है।हालांकि, खर्चे बाबत कोई आदेश के बिना ख़ारिज किया जाता है।

(25) चूंकि वर्तमान मुकदमा वर्ष 1996 में संस्थित किया गया था और इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं विद्वान विचारण न्यायालय से अनुरोध करना चाहूँगा कि वह मुकदमे का जल्द से जल्द फैसला करे।किसी भी मामले में तारीख से एक साल के भीतर इस आदेश की एक प्रति निचली अदालत के रिकॉर्ड में रखी जाती है।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरूग्राम, हरियाणा